



इस दशक का यह सबसे बड़ा उरवा!
किसानों के लिए कर्ज माफी महोत्सव!

रु. 1,50,000 तक
किसान कर्ज माफ



THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वार्ता



epaper.vaartha.com



इस दशक का यह सबसे बड़ा उरवा!
किसानों के लिए कर्ज माफी महोत्सव!

रु. 1,50,000 तक
किसान कर्ज माफ



वर्ष-29 अंक : 129 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) श्रवण कृ.11 2081 बुधवार, 31 जुलाई-2024

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर * पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये



इस दशक का सबसे बड़ा उत्सव! किसानों के लिए कर्ज माफी महोत्सव!



रु. 1,50,000 तक

किसान कर्ज माफ

सीधे किसान के ऋण खाते में जमा होगा

15 अगस्त, 2024 तक

रु. 1,50,000 से रु.2,00,000 तक ऋण माफ

प्रगति का पथ.. सभी का कल्याण.. जनता का शासन

कृषि विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रकाशित



वर्ष-29 अंक : 129 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) श्रवण कृ.11 2081 बुधवार, 31 जुलाई-2024

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH



epaper.vaartha.com

सेवानिवृत्त कैद्यों की पेंशन से जुड़ी सभी अड़चनें करें दूर
नई दिल्ली, 30 जुलाई (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कैद्यों को कड़ी फटकार लगाई। दससल, अदालत ने कुछ साल पहले वन रोज वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त न्यायमूर्त कैद्यों को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था। अगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर शीर्ष अदालत ने आज केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्त संजीव खन्ना और न्यायमूर्त आर महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक को समय दिया है। पीठ ने कहा कि दो लाख रुपये की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी।

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर * पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

GRAND *monsoon* SALE

FLAT 100%

at Pure Gold Rate
ON COMPLETE STOCK

NO making NO wastage



World's 1st Jewellery Showroom to present more than 100 exclusive Hallmarked Dulhan set's Certified by BIS

SHIVRAJ LAXMICHAND JAIN JEWELLERS

Exclusive Traditional & Designer Jewellery Collection

EXCLUSIVE DESIGNER • GOLD • DIAMOND • POLKI • SILVER • JEWELLERY COLLECTION - 2024

OLD GOLD EXCHANGE FACILITY AVAILABLE

6-3-1111/2, ADJACENT TO WESTSIDE SOMAJIGUDA CIRCLE, HYDERABAD. ☎ 96 80 916 916 / 83 84 916 916 / 63 09 916 916 / 97 80 916 916

SALE.. SALE.. SALE.. SALE.. SALE.. SALE.. SALE.. SALE..

शिवराज लक्ष्मीचंद जैन ज्वेलर्स में खरीदिए
916 स्वर्ण आभूषण शुद्ध सोने के भाव में....

DIAMOND JEWELLERY

FLAT 15% DISCOUNT
on diamonds

SILVER JEWELLERY

FLAT 20% DISCOUNT
on silver jewellery

SILVER UTENSILS

FLAT 50% DISCOUNT
on making charges

20000+
LATEST DESIGNS
READY TO EXPLORE

वायनाड में 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड, 125 मौतें मुझे अनुराग ठाकुर ने गाली दी है, इनकी माफी भी नहीं चाहिए : राहुल गांधी

वायनाड/नई दिल्ली, 30 जुलाई (एजेंसियां)। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए।

मुडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। 116 अस्पताल में हैं, जबकि 98 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्प्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम

> सेना और एयरफोर्स रेस्क्यू में जुटी > केरल में 2 दिन का राजकीय शोक



मौक मौक़े पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है।

एयरफोर्स के 2 हेलिकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना की स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेंड डाइंग, जिममें बेल्जियन मेनिनाइड्स, लेक्साइर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, वायनाड में भूखनन प्रभावित मेप्पाडी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर, केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। **>14**

नई दिल्ली, 30 जुलाई (एजेंसियां)। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक-दूसरे से जातीय जगणपना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा। इस दौरान सदन का माहौल काफी हंगामेदार रहा।

बता दें कि इस दौरान संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें बजट पर चर्चा हो रही है। इसी बीच जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 'अनुराग ठाकुर' ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। दरअसल, मंगलवार को सदन



में सभापति की कुर्सी पर जगदंबिका पाल बैठे थे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्हें पता होना चाहिए कि एलओपी व फुल फॉर्म लीडर ऑफ अपोजिशन होता है >14

बार काउंसिल में पंजीकरण के लिए युवाओं को ज्यादा ढीली नहीं होगी जेब : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 जुलाई (एजेंसियां)। कानून की पढ़ाई करने के बाद बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के लिए युवाओं को ज्यादा ज़ेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश और सभी राज्यों की बार काउंसिल को वकीलों के पंजीकरण के लिए कानून में तय शुल्क ही लेने के लिए दिए हैं। कई राज्यों में बार में पंजीकरण के लिए युवाओं से की जा रही मोटी फीस की वसूली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बार से सामान्य और अनासचित जाति-अनासचित जनजाति (एस-एस)



एस्टी) श्रेणी के विधि स्नातकों युवाओं से पंजीकरण के लिए क्रमशः 650 रुपये और 125 रुपये लेने के लिए कहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में विधि स्नातकों का बार में पंजीकरण करने के लिए बार काउंसिल मोटी फीस लेते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई विधि स्नातकों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कई राज्य

बार में पंजीकरण के लिए भारी-भरकम फीस ले रहे हैं। अत्यधिक पंजीकरण शुल्क वसूलना कानून का उल्लंघन है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। >14

टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को जमानत

नई दिल्ली, 30 जुलाई
(एजेंसियाँ)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेवशी तस्करों की मामले में दो साल के सख्त कारावास और फौजदारी मुकदमा के हिरासत में लिए गए तुम्फुल काकायेश (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दे दी। यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एसजी प्रशर्मा की पीठ ने लिया, जिन्होंने जमानत देने के लिए मुकदमे की लंबी अवधि को मुख्य कारण बताया। उन्होंने मंडल को चल रही जांच में पूरी सहयोग करने और जमानत की शर्त के रूप में अपना पासपोर्ट सौंपने को कानून की दिशा दिया।

गरीबी रेखा से बाहर आए 25 करोड़ लोग : पीएम मोदी



कि मैंने कहा था
मेरे तीसरे दर्ज में
देश तीसरे नंबर
की इकॉनमी
बनेगा।
लगातार सधे हुए
कदमों से आगे
बढ़ रहा है।
2014 में आपने
वा करने का मौका
4 में सरकार बनी
सफल पट्टी था कि
पसल पट्टी पर कैसे

लाए। पीएम मोदी ने कहा कि
पूँजीगत व्यय 10 वर्षों में पांच गुना
से अधिक होकर 11.11 लाख करोड़
रुपये के पार पहुँच गया है।
भारत ने पिछले 10 वर्षों में
मॉडलों के आवंटन में रिकॉर्ड
वृद्धि की है, जबकि कर की दरें
रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गई हैं।
सरकार जिस गति और स्तर पर
बुनियादी ढांचे का निर्माण कर
रही है वह अभूतपूर्व है। भारत हम
सेक्टर की इकॉनमी पर फोकस
कर रहा है। **₹14**

हमें देश की सेवा
दिया था। 201
तो सबसे बड़ा स
इकॉनमी को वा

आनन्द परिवार की ओर से परमपूज्य श्री आनन्दस्वरूपजी के 88वें जन्मजयन्ती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि-नमन



॥ जय श्री राम ॥

हमारे आदर्श परम पूज्यनीय
श्रद्धेय स्व.श्री आनन्द स्वरूपजी अग्रवाल



SINCE 1967



Badiya Quality
Badiya Swaad

a quality product from



A.P. PRODUCTS
PVT. LTD.

आदर्शों के लिए जिये, धर्म हेतु अर्पित जीवन ।
सदा सत्य का मार्ग चुना, स्वीकारों पावन वंदन ॥
आपकी स्मृति सदैव संस्कारों को प्रोत्साहन करती है ।

ANAND MASALA WARNING

It is hereby made known to all whom it may concern that the trade mark represented above had been invented, devised, originated and adopted by the predecessor-in-title of our clients, now known as **A P PRODUCTS PRIVATE LIMITED**, having their Registered Office at, Ground Floor, 8-2-293/82/J11/218/A, PH-3, Road No.78, Jubilee Hills, HYDERABAD - 500 033. Our Clients, by virtue of succession, are now the absolute proprietor of the trade marks duly Registered under the provisions of the Trade Marks Act, 1999 on all India basis in Class-30 starting with Registration Nos. 386785 & 386786, followed by many other registered adaptations of the same, in respect of **SPICES OF ALL KINDS**. All these registrations are valid and subsisting.

While so, it has come to our client's notice that **UNSCRUPULOUS** manufacturer and trader has been infringing, imitating and passing off the various adaptations of their registered trademarks and they accordingly filed relevant proceedings on the file of the VIII additional District Judge, Rangareddy, T.S. As a result one **YAGYANAND AGARWAL**, trading as **A P PRODUCTS**, of 18-7-445/1, 445/1A, 445/2, 445/6,7,8 & 9 Saraswati Nagar, Lalitabagh Road, Gowlipura Hyderabad - 500 053, **has by way of an INTERIM INJUNCTION ORDER** dated 11th November 2020 on IA No.447 in O.S. No. 283 of 2020, has been RESTRAINED from manufacturing, and selling and offering for sale, **SPICES OF ALL KINDS** either by himself, his servants, agents, under any identical, deceptively/phonetically similar to and/or a colourable imitation of clients' above REGISTERED TRADE MARKS and other registrations associated therewith. The said interim injunction Order was RESTORED by the Hon'ble HIGH COURT FOR THE STATE OF TELANGANA, HYDERABAD, after brief legal skirmishes, vide an Order dated 25/06/2021 on IA No.1 of 2021 in CRP NO.380 of 2021. The said Order is valid and subsisting as on date and the said **YAGYANAND / A P PRODUCTS** and his accomplices remain RESTRAINED from infringing and imitating and/or passing off the said Registered Trade Marks.

MANUFACTURERS, DISTRIBUTORS, STOCKISTS, RETAILERS & PRINTERS (PRESS OWNERS) dealing in such and cognate goods UNDER THE TRADE MARK "ANAND MASALA" in ANY ADAPTATION are hereby **WARNED** that any disobedience of the above INJUNCTION ORDERS issued by HON'BLE HIGH COURT FOR THE STATE OF TELANGANA, HYDERABAD shall amount to violation of the Injunction Orders leading for **CRIMINAL PROCEEDINGS, resulting in Police Raids, Arrests, Injunctions, Damages and Compensatory Damages.** Let all persons govern themselves accordingly.

Dated: December 22, 2021
Place: Hyderabad

Sd/- (V.K.SINHA) Advocate & Attorney
THE GLOBE TRADING COMPANY Trade Mark Attorneys & Advocates,
#5-9-93, No.208, 2nd Floor, Shakti Chambers, Chapel Road, HYDERABAD - 500 001. T.S
Phone : 040 23232385, 23300342, Mobile 98480-34051

CAUTION !!! TAKE CARE

ORIGINAL PACK

A.P. PRODUCTS PVT. LTD.



दुप्लीकेट पैक को न
मासुनें कंठें



DUPLICATE PACK BY
A.P. PRODUCTS

संस्थापक न्यासी:
वेदप्रकाश अग्रवाल
फोन : 9849655105,
लाला राम शरण दास
आनन्द स्वरूप धर्मार्थ न्यास
18-7-445/1, सरस्वती नगर,
गौली पूरा, हैदराबाद

संस्थापक न्यासी, अध्यक्ष व संचालक :
वेदप्रकाश अग्रवाल
फोन: 9849655105,
गंगा-राम धर्मार्थ न्यास,
श्री गंगा-राम शिक्षा समिति व
भागीरथी देवी महाविद्यालय,
मंडी धनौरा, उत्तर प्रदेश-244231

वेदप्रकाश अग्रवाल - 9849655105 विवेकानन्द अग्रवाल - 9848053144 विपुलानन्द अग्रवाल - 9848885325 शिवानन्द अग्रवाल - 9246351879 विष्णुानन्द अग्रवाल - 7036228855

| | | | |
|--|--|--|---|
| Registered Office A.P. PRODUCTS PVT. LTD. Jubilee Hills, BHAGYA NAGAR, Hyderabad - 500 033 - TS, BHARAT (INDIA). | BHARATIYA ANAND & FOOD PRODUCTS #18-7-445/10, Saraswathi Nagar, Gowlipura, Bhagyanagar (Hyd) 500 053, T.S., | A.P. PRODUCTS PVT. LTD. #18-7-445/1, 1A, 2, 6,7,8,9 Saraswathi Nagar, Gowlipura, Bhagyanagar (Hyd) 500 053, T.S., | anandmasalaapplt@gmail.com Customer Care: 1800-121-2139 www.anandmasala.com |
|--|--|--|---|

श्री आनन्द मसाला भंडार

#15-7-407-411, बेगमबाग, हैदराबाद-12.
फोन : 9848053144, 9848885325

REQUIRED DISTRIBUTORS AND MARKETING PERSONS. INTERESTED PERSON PLEASE MAIL TO : anandmasalaapplt@gmail.com, WITH ALL DETAILS

बुधवार, 31 जुलाई, 2024 5

अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

दो कांस्टेबल, एक होमगार्ड समेत 9 गिरफ्तार



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। एस.एम. विजय कुमार, डीसीपी पश्चिमी क्षेत्र, हैदराबाद और एस. मोहन कुमार, एसीपी, पंजागुडा डिवीजन की देखरेख में मेट्रो ट्रेनों में हाल ही में हुई मोबाइल चोरी के मामलों में उपलब्ध सुरागों पर काम करते हुए, पंजागुडा पुलिस को एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह के बारे में पता चला जिसमें छह आरोपी शामिल थे, जिन्हें एमएस मक़ता में एक होमगार्ड और दो कांस्टेबल के साथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उनके कब्जे से 15 फोन जब्त किए गए।

आरोपियों ने कबूल किया कि गिरोह का मुख्य सरगना झारखंड राज्य के थेनपहाड़ से गांव का राहुल कुमार यादव है जिसने एक

गिरोह बनाया है और गिरोह के सदस्यों को देश के विभिन्न हिस्सों जैसे हैदराबाद, सूरत, लखनऊ, रांची, बेलूर, चेन्नई, वाराणसी, नागपुर, पटना में तैनात किया है। गिरोह के सदस्य सस्त्री मंडियों, मेट्रो ट्रेनों, धार्मिक जुलूसों आदि जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों की पहचान करते हैं। गिरोह के सदस्य उक्त जगहों पर घूमते हैं और भोले-भाले पीड़ितों की पहचान करते हैं जो अपने सेल फोन को शर्ट की जेब में रखते हैं और जब गिरोह के सदस्य एकाग्रता भंग करने के लिए कवर देते हैं, तो गिरोह का एक प्रशिक्षित व्यक्ति पीड़ितों की जेब से सेल फोन उठाता है और गिरोह के किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है। चोरी करने के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरोह के सभी सदस्य जगह

से चुपके से निकल जाते हैं और वे सेल फोन की चोरी करते हैं तो वे गिरोह के सरगना राहुल कुमार यादव को सूचित करते हैं। वह एक अन्य व्यक्ति मुक्तार सिंह को हैदराबाद और अन्य शहरों में मोबाइल इकट्ठा करने और उन्हें झारखंड लाने के लिए भेजता है और वे दोनों एक साथ पश्चिम बंगाल जाते थे। गद्दी नगर थाने में कार्यरत पुलिस कर्मी अशोक एचजी और पीसी सोमन्रा तथा सैफाबाद थाने में कार्यरत साई राम पीसी ने गिरोह के सदस्यों से पैसे लेकर उन्हें पुलिस थानों से छुड़वाने में मदद की। आरोपी व्यक्तियों में अलामिनगाजी उर्फ जिंदी नोनिया

अतुरिया, उत्तरी परगना, पश्चिम बंगाल, मोहम्मद शाहनवाज निवासी दौना, पोस्ट-बाकछप्पर, शाहकुंड, बाघछप्पर, भागलपुर, बिहार, गोविंदा कुमार महतो, निचे टोला, तीनपहाड़, साहेबगंज, झारखंड, जुगेश्वर नोनिया निवासी बाबूपुर, तीनपहाड़, साहेबगंज, झारखण्ड, जौनू कुमार पुत्र, निवासी कजरैली, भागलपुर, कजरैली, बिहार, मोहम्मद मुख्तार शेख निवासी तिनपन्हार, साहेबगंज, झारखंड, के. अशोक, एचजी, पी.एस. गांधी नगर, निवासी चेंगिचेरला, हैदराबाद, पी. सोमन्रा पुलिस कांस्टेबल, गांधीनगर, निवासी अंबरपेट, साई राम, पुलिस कांस्टेबल , सैफाबाद निवासी चिलकलगुडा, हैदराबाद शामिल हैं। जबकि कंचन नोनिया निवासी बाबूपुर तिनपहाड़ गांव, साहेबगंज जिला, झारखंड, शानू निवासी तिनपहाड़, साहेबगंज, झारखंड, राहुल कुमार यादव निवासी तिनपहाड़, साहेबगंज जिला, झारखंड, रिंकू निवासी तिनपहाड़, साहेबगंज जिला, झारखंड फरार हैं। आरोपित के पास 15 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस ने जगता से अपील करते हुए कहा है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें। पीड़ित अपनी इसी तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। संदेह की स्थिति में, लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन/निग्रंथ कक्ष 8712660000/डायल 100 पर संपर्क कर सकते हैं।



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। उत्तरी क्षेत्र पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) द्वारा उत्तरी क्षेत्र के एसएचओ के साथ उत्तरी क्षेत्र के सम्मेलन कक्ष में समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के सभी 11 पुलिस थानों की सीमाओं से आवासीय कल्याण संघों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बैठक का उद्देश्य निवासियों की पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न चिंताओं को समझना और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ निर्देश देना था। प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटों का काम न करना, सीसीटीवी कैमरों का न होना, नाबालिगों द्वारा वाहनों की सवारी करना, सड़कों पर अनधिकृत/अनियमित पार्किंग, जिससे मुक्त मार्ग अवरुद्ध होता है, लापरवाही से वाहन चलाना, स्ट्रीट डॉग, आवासीय कॉलोनियों के बगल में कचरा फेंकना, आवागार लोगों की सदिग्ध गतिविधियाँ, सड़क विक्रेताओं द्वारा सड़कों/फुटपाथों पर अतिक्रमण आदि। इन चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई और

उत्तरी क्षेत्र पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नागरिकों की सुरक्षा, कॉलोनी परिसर में सीसीटीवी लगाने और घर में चोरी के खिलाफ एहतियाती उपायों से संबंधित निर्देशों पर चर्चा की गई। उनका सहयोग मांगने के अलावा, रजिस्टर्ड एसोसिएशनों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया, खासकर जहां वरिष्ठ नागरिक अकेले रह रहे हैं और किराए की मदद से उनकी सेवा की जा रही हो।

अग्नि सुरक्षा, विद्युत उपकरण ऑडिट, अग्नि अभ्यास, सीसीटीवी कवरेज की आवश्यकता, पड़ोस के बारे में जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस उपायुक्त, उत्तर क्षेत्र, हैदराबाद सुश्री एस रश्मि पेम्पल ने कहा कि प्रत्येक आरडब्ल्यूए से नोडल अधिकारी वाला एक समूह भी बनाया जाएगा जो सभी आरडब्ल्यूए को महत्वपूर्ण जानकारी का आसान प्रसार सुनिश्चित करेगा और किसी भी मुद्दे को तुरंत हल करने में मदद करेगा।

बीसी घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर धरना

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। हाल ही में घोषित बजट में बीसी के साथ कांग्रेस सरकार के अन्याय के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद गौड़ के नेतृत्व में बीसी घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए हैदराबाद कलेक्टरेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष शांति कुमार समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष शांति कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हाल ही में घोषित बजट में बीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। झूठ के आधार पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी में घोषित बीसी घोषणा को लागू करने से बचने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने स्थायी निकायों में मौजूदा बीसी आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे नहीं बढ़ाया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने उपयोग के तहत हर साल 20 हजार करोड़ रुपये देने का वादा किया और बजट में अन्याय किया। उन्होंने कहा कि वे बीसी के युवाओं को छोटे व्यवसाय चलाने और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का असुरक्षित और ब्याज मुक्त ऋण देंगे। शांति कुमार ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि जब तक कांग्रेस पार्टी बीसी से किए गए वादों को पूरा नहीं करती, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई तेज करेगी।



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। श्रौशैलम परियोजना में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन बाढ़ का पानी घुसना जारी रहा। परियोजना से 2.25 लाख क्यूसेक से अधिक बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है। इसके लिए दो और गेट खोले गए हैं। इसके अलावा तीन गेट पहले से ही खुले रखे गए थे, ताकि पानी का प्रबंधन किया जा सके। कृष्णा में बाढ़ के स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि वर्तमान भंडारण 215 टीएमसी की सकल भंडारण क्षमता के मुकाबले 203 टीएमसी तक पहुंच गया है। जलाशय का स्तर 882 फीट (885 फीट के एफआरएल के करीब) तक पहुंच गया है।

श्रीशैलम में दो और गेट खोले गए



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री डी. अनसूया उर्फ सीथक्का ने बीआरएस सदस्य अनिल कुमार जाधव की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई कि उनके माता-पिता को पोड़ू भूमि का स्वामित्व दस्तावेज बीआरएस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के कारण मिला था। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता को पट्टा कानून के अनुसार मिला था, किसी पक्षपात के कारण नहीं।

सीताक्का के माता-पिता को पिछले वर्ष मुलुगु मंडल के जगन्नाथरा गांव में 1.17 एकड़ जमीन का पट्टा मिला था, जब बीआरएस सरकार ने पोड़ू भूमि मालिकों को पट्टा सौंपने का निर्णय लिया था। मंगलवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सीतक्का ने जाधव के इस दावे का भोजन और रात का खाना- ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड दोनों), पेशेवर और मैत्रीपूर्ण दूर एस्कॉर्ट्स की सेवाएं, ट्रेन में सुरक्षा (सभी कोचों में लगे सीसीटीवी कैमरे सहित), सभी कोचों में सार्वजनिक घोषणा की सुविधा, यात्रा बीमा और सहायता के लिए पूरी यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी रू मैनेजर की मौजूदगी शामिल है।

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 और 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। यह सम्मेलन राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, शिक्षा, जनजातीय मामले, सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, युवा मामले एवं खेल मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सीईओ, पीएसओ, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में तीन आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता, आदिवासी क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास, 'मेरा भारत', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'एक वृक्ष मां के नाम' जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका, प्राकृतिक खेती, जनता से संपर्क बढ़ाना, राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका शामिल है। राज्यपाल अलग-अलग समूहों में इन एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुति देंगे।

वीएच ने उप्पल स्टेडियम में राजीव की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मंगलवार को पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व सांसद वी. हनुमंत राव ने एसएएपी अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी और उप्पल कांग्रेस पार्टी प्रभारी परमेश्वर रेड्डी के साथ उप्पल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भूमि पूजन किया, जहां वीएच पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर बोले हुए, वीएच ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पर किया जाएगा। पूजा में पीसीसी महासचिव आर. लक्ष्मण यादव, पीसीसी सचिव अफसर सुसुफ, शंभुला श्रीकांत गौड़, ज्ञानेश्वर गौड़, आदि अविनाश और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया।

सीतक्का ने माता-पिता का नाम लिए जाने पर जताई आपत्ति

कानून के अनुसार मिला था पट्टा, बीआरएस की वजह से नहीं

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री डी. अनसूया उर्फ सीथक्का ने बीआरएस सदस्य अनिल कुमार जाधव की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई कि उनके माता-पिता को पोड़ू भूमि का स्वामित्व दस्तावेज बीआरएस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के कारण मिला था। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता को पट्टा कानून के अनुसार मिला था, किसी पक्षपात के कारण नहीं।

सीताक्का के माता-पिता को पिछले वर्ष मुलुगु मंडल के जगन्नाथरा गांव में 1.17 एकड़ जमीन का पट्टा मिला था, जब बीआरएस सरकार ने पोड़ू भूमि मालिकों को पट्टा सौंपने का निर्णय लिया था। मंगलवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सीतक्का ने जाधव के इस दावे का भोजन और रात का खाना- ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड दोनों), पेशेवर और मैत्रीपूर्ण दूर एस्कॉर्ट्स की सेवाएं, ट्रेन में सुरक्षा (सभी कोचों में लगे सीसीटीवी कैमरे सहित), सभी कोचों में सार्वजनिक घोषणा की सुविधा, यात्रा बीमा और सहायता के लिए पूरी यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी रू मैनेजर की मौजूदगी शामिल है।



पर नाराजगी जताई कि उनके माता-पिता को पूर्व मुख्यमंत्री की वजह से पट्टे मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता पांच दशकों से अधिक समय से जमीन पर खेती कर रहे थे, उन्हें कानून के अनुसार पट्टे मिले थे, न कि बीआरएस सरकार की वजह से।

मंत्री ने कहा कि पट्टा यूपीए सरकार द्वारा लाए गए वन अधिकार अधिनियम-2006 के अनुसार उसके माता-पिता को दिया गया था और बीआरएस सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। जाधव ने स्पष्ट किया कि वह मंत्री का अमानान नहीं करना चाहते थे, बल्कि बीआरएस सरकार की उपलब्धियों में से एक का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा मंत्री की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सिर्फ उनके माता-पिता

प्रजावाणी कार्यक्रम में कुल 455 आवेदन प्राप्त हुए

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में कुल 455 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य संबंधी 94, नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित 77, विद्युत विभाग से संबंधित 45, आवास से संबंधित 44, पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 40 तथा अन्य विभागों से संबंधित 155 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. चित्रा रेड्डी ने भाग लिया और आवेदन प्राप्त किये। उन्होंने प्रजा भवन में आये लोगों से उनकी समस्याएं पूछीं।

केटीआर ने पूछे कांग्रेस सरकार से सवाल

याद दिलाया कि अतीत में कांग्रेस नेता कोदंडा रेड्डी, कोमाटिरेड्डी वेंकटर रेड्डी, श्रीधर बाबू और सीएम रेवंत रेड्डी ने घोषणा की थी कि फार्मा सिटी की जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। विधानसभा में वार्षिक बजट के मदों पर चर्चा के दौरान केटीआर ने पूछा कि अगर फार्मा सिटी को खत्म कर दिया गया तो किसानों को जमीन कब लौटाई जाएगी। केटीआर ने मुसी नदी सौंदर्यकरण परियोजना की लागत में भारी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सीवीजे ट्रीटमेंट प्लांट पर 100 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है,

और मुसी सौंदर्यकरण 16,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने सरकार से लोगों को जवाब देने को कहा कि उसने मुसी नदी परियोजना की लागत 1,50,000 करोड़ रुपये तक क्यों बढ़ा दी? केटीआर ने सरकार से परियोजना की डीपीआर जनता के सामने रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हैदराबाद में एसआरडीपी और एसएनडीपी परियोजनाओं पर काम पूरी तरह रुका हुआ है। पिछले आठ महीनों से फ्लॉडओवर और पुलों का निर्माण बंद है। यह कहते हुए कि बिलों का भुगतान न करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, केटीआर ने सरकार से तुरंत बिलों का भुगतान करने और काम पूरा करने का आग्रह किया।

आरटीसी कर्मचारियों की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर है : पोन्नम

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को कहा कि टीजीएसआरटीसी कर्मचारियों की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने ही नवोद्य और गुरुकुलम की शुरुआत की थी और कहा कि वहां से पढ़कर आए कई लोग आज उच्च अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने विधानसभा में जोश से बात की और बीआरएस पार्टी के शासनकाल में हुए आरटीसी टैंडरों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि आरटीसी, जो महत्वपूर्ण हो गया है, आज उनकी सरकार द्वारा धीरे-धीरे विकसित किया जा रहा है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीआरएस पार्टी जिसने कहा था 'आरटीसी नहीं चलेगा' आज आरटीसी पर मागमच्छ के आंसू बहा रही है।

न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर विद्युत आयोग के अध्यक्ष बने

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर को तेलंगाना विद्युत आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तेलंगाना सरकार ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी ने आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

रेवंत रेड्डी सरकार ने याददारी और भद्राद्री सब-क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने और छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीदने के लिए तेलंगाना में पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी को नियुक्त किया गया। जांच के दौरान पूर्व सीएम केसीआर ने आयोग के गठन और इसके अध्यक्ष की निष्पक्षता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी को बदलने का आदेश दिया।

CLASSIFIEDS CHANGE OF NAME

I, SUNITA GHATANI Legal W/o. SUDESH GHATANI Vid No.14940115H, Rank -NK, R/O Naya Railway siding Rangbulla ha, PO-Rangbulla ha, PS. Jorabunglow, Dist. Darjeeling, W.B., INDIA-734123, hereby declare that, due to my name wrongly mentioned in service document of my husband, I have changed my name from SUNITA GHATANI to SUNITA GAZMER Vid Affidavit No.3204/224, dt. 15/05/2024 Hence from now onwards I will be known as above changed name for all purposes.

I, NEERAJ KAWAR , Legally wedded Spouse of SHEKHAWAT BAIRANG SINGH, R/O: KOTRI, SRIMADHOPUR, SIKAR, RA-JASTHAN - 332715, have changed my name from NEERAJ KAWAR to NEERAJ KANWAR vide Affidavit dt.23-7-2024 duly Sd.by P.RAVEENDRANATH ADV & NOTARY

आवधान
पाठकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक विज्ञापन का प्रतिवादन करने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। विज्ञापनदाता ने दावा कर रहे हैं या कह रहे हैं, इन बातों से दैनिक समाचार पर (स्वतंत्र वार्ता) का किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है।

स्वतंत्र वास्तव

बुधवार, 31 जुलाई- 2024

तीन मौतों से क्या सबक लिया?

दिल्ली के राजेंद्रनगर में लोक कोचिंग में आईएसएस बनने की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की दुखद मौत ने जहां देश को हिला दिया वहीं स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व पर भी जमकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्रनगर और मुखर्जी नगर कोचिंग हब के रूप में विख्यात है। लाखों लोग देश भर से इन कोचिंग क्लासों पर विश्वास कर पढ़ने आते हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर हालात कितने बदतर हैं यह भी किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वह प्रशासन हो या राजनेता। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होना लापरवाही नहीं तो और क्या दर्शाता है? तीन होनहार युवाओं की मौत के बाद अब गिरफ्तारियों और निलंबन की रस्मअदायगी की जा रही है। राजधानी में यूपीएससी त्रैक करने की आकांक्षा लेकर आए तीन स्टूडेंट्स की जिन हालात में मौत हुई, वह दुखद तो है ही, बेहद शर्मनाक भी है। इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनटेनेंस से जुड़े तमाम विभागों और उनके कर्मचारियों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इनके संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद ही स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व नींद से जागा है। नतीजतन अपना पिंड छुड़ाने के लिए धड़ाधड़ कई गिरफ्तारियां कर ली गईं बल्कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी और निलंबन जैसे कदम उठाते हुए घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। संसद में भी यह मामला उठाकर कार्रवाई की मांग की गई है। कोफ्त होती है कि जिस हालात की वजह से यह दुखद घटना हुई है वह कोई नई नहीं है। न ही ऊपर से लेकर नीचे तक के सरकारी तंत्र का कोई भी हिस्सा इन हालातों से अनजान है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्रनगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाके आईएसएस कोचिंग हब के रूप में काफी पहले से जाने जाते रहे हैं। वहां जीर्ण-शीर्ण इमारतों में किन हालात में कोचिंग सेंटर चलते हैं और स्टूडेंट्स प्रतिष्ठित सेवाओं की तैयारी करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इससे पहले ही आग लगने जैसी घटनाएं उन विषम हालात की ओर सबका ध्यान खींच चुकी हैं। लेकिन तब भी शासन व प्रशासन नहीं चेता। वाजिब सवाल यह है कि जब सबको पहले से यह सब पता था, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब भी क्या गारंटी है, कुछ समय बाद फिर सबकुछ पहले जैसा ही नहीं हो जाएगा। यही इस पूरी घटना का सबसे गंभीर पहलू है और इसी बिंदु पर सरकार व शासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। घटना के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरह एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया, वह भी निराश करने वाला है। जहां बीजेपी इसके लिए एमसीडी और राज्य की सत्ता संभाल रही आप को यह कहते हुए जिम्मेदार बता रही है कि सारे संबंधित विभाग इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं, वहीं आम नेताओं का कहना है कि तमाम अफसरों को दंडित या पुरस्कृत करने का अधिकार तो एलजी के हाथों में थमा दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसी हर त्रासदी पर राजनीति दिल्ली के लोगों की निशानि है या कोई आगे बढ़कर इनकी जिम्मेदारी भी लेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न होने देने का संकल्प भी करेगा। आखिर इन तीन युवाओं की मौत का कौन जिम्मेदार होगा इसे कौन तय करेगा?

बाढ़ की प्राकृतिक त्रासदी

पानी के उत्प्लवन से दिल्ली का सदैव बुरा हाल रहा है। दिल्ली शहर में वर्षा के पानी के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में में जल भराव से तीन युवा छात्रों की मौत ने छात्र जगत में हाहाकार मचा दिया है, जब जाकर **संजीव ठाकुर** ली जा सकती है। क्योंकि जापान आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। जापान में आपदा से निपटने के लिए विभिन्न प्रयासों, विकास कार्यक्रमों में योजनाओं पर बढ़ाने औरसरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए 'यूपी फॉर यूथ, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोबल' की कल्पना के बारे में बताया मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश का समय है । उत्तर प्रदेश अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए देश के बहुआयामी विकास के सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित होगा । यूपी की क्षमता के अनुरूप क्षेत्रवार अल्ट्राकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री

तकनीक को याकोहामा रणनीति कहा जाता है। जापान में आपदा प्रबंधन की साल भर नियमित रूप से डॉमिनैरिंग कर एक्सरसाइज की जाती रहती है, एवं आपदाओं पर निरंतर निगरानी तथा नजर रखी जाती है, एवं इसके निदान के लिए पूर्व से ही सुनियोजित योजना बनाकर नागरिकों को सुरक्षित कर लिया जाता है। भारत को भी इसी तरह आपदा प्रबंधन को अपनाकर हमें बाढ़, अतिवृष्टि, लैंडस्लाइडिंग तथा भूकंप से पूरी क्षमता कथा विशेषताओं के साथ सामना करना चाहिए। आपदाओं के प्रति मानवीय सभ्यता के संदर्भ में समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को ज्यादा प्रभावित करती है। एवं समाज का सबसे संवेदनशील तबका यानी वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं, बच्चों, दिव्यांग लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। आपदा के समय सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग का व्यक्ति तथा मजदूर तबके का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होकर उसकी दिनचर्या समूह रूप से छिन्न-भिन्न हो जाती है, एवं आर्थिक साधन भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे आजीविका का एक बड़ा भय सताने लगता है। भारत के भू भाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें हिमालयिन क्षेत्र,पूर्वोत्तर राज्य, गुजरात का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से सबसे सक्रीय क्षेत्र रहे हैं। देश के 65 से 68% भूभाग पर कभी कम कभी ज्यादा भीषण रूप से सूखा पड़ता है, इसी तरह भारत के पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्य में मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क न्यून नमी वाले क्षेत्र सूखे से सदैव प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित भूमि का विस्तार क्षेत्र देश के 12% है।

देवेन्द्र फडणवीस से क्यों डरा रहता है विपक्ष?



आर.के.सिन्हा

लोकसभा चुनावों के नतीजे आने और केन्द्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब महाराष्ट्र

विधानसभा के आगामी अक्तूबर के महीने होने वाले चुनाव है। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की जान है महाराष्ट्र। इसलिए सारे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी रहती हैं। वहां राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति भी गरमा चुकी है। आरोप-प्रत्यारोप के नियमित दौर चल रहे हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष महाविकास आघाड़ी राज्य के उस नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जिसने राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का चौरफा विकास करवाया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शिखर भाजपा नेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस राज्य के एक बड़े नेता होने के साथ ही काफी दूरदर्शी और अनुभवी रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। वह कई बार मुश्किलों में फँसी पार्टी को बाहर निकालकर अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में कई काम हुए। मुंबई मेट्रो विस्तार और मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तब महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में आई और बढ़ी। देवेंद्र फडणवीस ने ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिसिंग को मजबूत

किया और अपराध की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेटेड सिस्टम की शुरुआत की। समाज कल्याण को लेकर भी उन्होंने काफी पहल की। हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू किए गये। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीत दिनों देवेन्द्र देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वे जब राज्य के गृहमंत्री थे तब उन्होंने (देवेंद्र फडणवीस ने)उन पर दबाव बनाया था कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के तीन अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवा दें। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख का इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। कुल मिलाकर लग यह रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता के बुनियादी मसलों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे। विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए तबीयत से कीचड़ उछालेगा। जाहिर है फडणवीस ने भी देशमुख को उनकी ही भाषा में जवाब भी दिया। सबको याद है कि अप्रैल 2021 में गृह मंत्री रहे देशमुख पर तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिन्गर परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से पैसे वसूलने पर लगा दिया था। अब देशमुख कह रहे हैं कि फडणवीस के निदेश पर परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। अब तीन साल बाद वही एनसीपी नेता देशमुख यह दावा कर रहे हैं कि फडणवीस ने उन पर उद्धव और आदित्य ठाकरे, तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री

अनिल परब सहित एमवीए के प्रमुख लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला था। साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टकराव बढ़ने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस ज्यादा रहने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता रणनीति के तहत हल्ला बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को घेरकर वे विधानसभा चुनाव में बढ़त बना सकते हैं। वेशक, यह अफसोसजनक स्थिति है कि जिस फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, उन पर मिथ्या आरोप लग रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में मुंबई मेट्रो का विस्तारीकरण हुआ। मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग, आर्थिक गलियारों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत हुई। बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए किरायाती आवास योजनाओं को उन्होंने ही लागू किया। सड़क और रेल परियोजनाओं सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार किया। आतंकवाद-रोधी उपायों के तहत संभावित खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए सुरक्षा ढांचे की बढ़ावा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया। मुंबई ट्रांस हॉबर् लिंक के तहत मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए इस समुद्री पुल की शुरुआत की। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने राज्य भाजपा को एकजुट किया। यह फडणवीस ही थे

जिन्होंने भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना के बिना चुनाव लड़ने का हिम्मती फैसला किया। उन्होंने राज्य के लिए भाजपा की स्वतंत्र ताकत और दृष्टि पर जोर दिया और उनके नेतृत्व में ही भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राज्य में शिव सेना के निहा भाजपा की सरकार बनाने के लिए फडणवीस ने ही मंच तैयार किया। अब भी वह सत्तासीन गठबंधन में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका रणनीतिक कौशल जबर्दस्त रहा है। वह शासन में निरंतरता और प्रगति सुनिश्चित करते हुए लक्ष्योपेन के साथ हर मुद्दे का राजनीतिक समाधान तलाशने में महारत रखते हैं। वही विभिन्न वर्गों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में आगे रहे हैं। उनकी नेतृत्व शैली और उपलब्धियों ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। वह पैराशूट वाले नेता नहीं हैं। महाराष्ट्र में वह भाजपा में रैक के माध्यम से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। फडणवीस 1989 में युवा विंग के अध्यक्ष रहे हैं और केवल 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर नियुक्त हुए और 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वह एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस दोनों में स्वीकार्यता रखते हैं। वह संघ के मूल मूल्यों को समझते हैं और पार्टी के भीतर उसको अपनाने की कोशिश भी करते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्थिति को स्थिर करने और पार्टी के हितों की रक्षा सुनिश्चित

करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हाल के लोक सभा चुनावों में पार्टी की हार को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए इस्तीफा देने की उनकी पेशकश, नीतिक बल को ही दर्शाती है। फडणवीस पर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य के राजनीतिक हलकों में कई लोगों को लगता है कि पिछले दस वर्षों से महाराष्ट्र में भाजपा के निर्विवाद नेता के रूप में फडणवीस ही राज्य में भाजपा की पुनः वापसी कर सकते हैं। वे विपक्ष की पटकनी देने में सक्षम हैं। विपक्ष भी हमेशा फडणवीस से ही डरा हुआ दिखाई देता है। किसी न किसी तरह से उन पर निशाना साधने में महाविकास अघाड़ी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेन्द्र फडणवीस पर भरोसा रखते हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, सबको लगा कि फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ गए। उन्हें अपने पुराने सहयोगी - भारतीय जनता पार्टी को दगा देने में कोई संकोच नहीं किया। शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व को राजी किया और उन्हें उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए मजबूर किया और अपनी सरकार बना ली, लेकिन फडणवीस ने जून 2022 में पवार साहब की साजिश को माकूल जवाब दे दिया। केवल ढाई साल की अवधि के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। अब वही ठाकरे शरद पवार के हाथों खिलौना बने हुए हैं।

मोदी के सपने को पूरा करने का रास्ता यूपी से ही जाता है



अशोक भाटिया

भाजपा की मुख्य मंत्रों की बैठक दो दिन पहले ही समाप्त हुई है। बैठक में कई

राज्यों की योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। इसमें भाजपा शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उपमुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें जन कल्याण के लिए समन्वित प्रयासों के साथ काम करें तो सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विरासत का संरक्षण और विकास की विरासत का निर्माण विकसित भारत की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को इस ओर ध्यान देते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, विकास कार्यक्रमों में योजनागिदारी बढ़ाने औरसरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए 'यूपी फॉर यूथ, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोबल' की कल्पना के बारे में बताया मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश का समय है । उत्तर प्रदेश अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए देश के बहुआयामी विकास के सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित होगा । यूपी की क्षमता के अनुरूप क्षेत्रवार अल्ट्राकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री

की संख्या में सबसे अधिक गिरावट वाले राज्यों में यूपी शीर्ष पर है । यूपी में गरीबी में सर्वाधिक कमी वाले जिले महाराजगंज (29. 64%), गोंडा (29. 55%), बलरामपुर (27. 9%), कौशांबी (25. 75%), लखीमपुर खीरी (25. 33%), श्रावस्ती (24. 42%), जौनपुर (26. 65%), बस्ती (23. 36%), गाजीपुर (22. 83%), कुशीनगर (22. 28%) और चित्रकूट (21. 40%) है । जो लोग यूपी को जानते हैं वे आपको बताएंगे कि इन जिलों की हालत पहले बहुत खराब थी. इसलिए यदि राम और कृष्ण की जन्मस्थली यूपी से दिल की छू लेने वाली ऐसी सुखद खबर आ रही है तो यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक शुभ संकेत है । बीमारू राज्य शब्द का प्रयोग अक्सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने के लिए किया जाता रहा है । आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य सभी सूचकांकों में पिछड़े हुए हैं । भारत की यदि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना भी अति आवश्यक है. यह भी सत्य है कि नए परिसीमन के चलते उत्तर प्रदेश नए मुकामले राजनीतिक रूप से आज अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । भारत के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़ी भूमिका के निर्वहन में यूपी, समाज के विभिन्न स्तरों के साथ राजनीतिक नेतृत्व के जरिए योगदान दे सकता है। यदि उत्तर प्रदेश नेतृत्व करे तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सकता है । यूपी को आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, आईपी और एआई के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, रक्षा

उत्पादों के निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स सरीखे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा । नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि 2015-2016 से 2019-2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूपी) में उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई । राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चला है कि इस अवधि के दौरान 13. 5 करोड़ लोगों में से अकेले यूपी में 3. 43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले । यह एक चौंका देने वाली संख्या है । 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों पर केंद्रित रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सबसे तेज गति से गरीबों की संख्या में कमी का इशारा करती है । गरीबी कम होने के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य यूपी के बाद ही आते हैं । सरकार ने दावा किया है कि रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि राज्य भर के गांवों में गरीबों की संख्या तेजी से घटी है । इतना ही नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता सरीखे मानकों पर भी बेहतरीन परिणाम दिखे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आगरा के उद्यमी और रोटरी क्लब के प्रमुख मनीष मित्तल कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साहजनक माहौल है । राज्य सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है । मेरा विश्वास करें, हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और हम आर्थिक विकास में एक लंबी छलंग लगाते के लिए तैयार हैं। हमाल के इच्छुक लोगों के लिए काम की कोई कमी नहीं है । नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, पोषण से वंचित गरीबों की संख्या 2015-16 में 30. 40% से घटकर 2019-21 में 18.45% रह गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर में 3. 81% की कमी है जो 2015-16 में 31. 20% से गिरकर 2019-21 में 2. 20% हो गई है ।

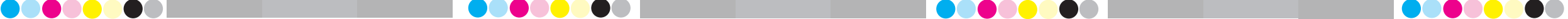
ममता का कत्ल! यह हैवानियत कहाँ से आ रही



मनोज कुमार अग्रवाल

अभी शनिवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी नौ दिन की मासूम बेटी को दिल्ली के मुंडका इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी नौ दिन की मासूम बेटी को

लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। 4 अप्रैल यमुनानगर के एक इलाके में एक महिला ने कथित तौर पर अपने एक महीने के बेटे की हत्या कर दी। नवजात का शव यमुनानगर की शिवपुरी-बी कॉलोनी स्थित महिला के घर में पड़ा मिला। गांधी नगर पुलिस ने कहा कि बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम आज मुकंद लाल जिला सिविल अस्पताल, यमुनानगर में किया गया। 9 अप्रैल को रायगढ़ में एक विवाहिता ने पांच और 3 साल के दो बच्चों को मार डाला। 10 दिन बाद पुलिस ने मां को पकड़ा, बोली- 'प्रेमी के लिए किया' रायगढ़ पुलिस ने एक 25 साल की महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने हत्या की बात कबूल की। 28 जून औरैया जिले में एक महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार करने और खर्चा उठाने से मना कर दिया गया था। इस वजह से महिला अपने 4 बच्चों को लेकर नदी किनारे पहुंची और 2 को पानी में डुबोकर गंगा दबाकर की हत्या कर दी। तीसरे छोटे बच्चे को पानी में फेंक दिया था। इस वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन चौथे बच्चे ने मरने का नाटक करते हुए अपनी जान बचाई। वहीं, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 बच्चों की हत्यारिण मां को इसका चचेरे देवर को गिरफ्तार किया । 26 जून पिता के लिए उसका बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है बिहार के पटना में एक पिता ने अपने ही दो साल के बेटे की हत्या करने के बाद शव को घर से दूर फेंक दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बच्चे की मां के बयान पर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। हाल ही में 10 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दो मासूम नवजात बच्चियों की हत्या मामले में फरार चल रहे पिता को गिरफ्तार किया है। घटना का पता तब चला था जब आरोपी का साला उनके घर आया। आरोपी की पत्नी उस वक्त मायके में थी। उसे भनक भी नहीं थी कि उसके पति ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी दो बेटियों को मार डाला। आरोपी पिता बच्चियों को मार डालना चाहता था। इसलिए उसने बच्चियों को दो दिन तक दुध की बूंध भी नहीं पिलाई। भूख रहने के कारण मासूमों की मौत हो गई। चुपचाप दोनों बच्चियों के शवों को दफना दिया। साले को जीजा पर शक हुआ। उसने पुलिस को इस बारे में बताया। तब पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया।



पीएम आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा आवास

रायपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वैंसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी ख़ा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति

सीएम साय ने की केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात



नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने के अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों

के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10 हजार 500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग

की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। सीएम साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।

आर्मी लैंड स्कैम केस में आईएसएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका

जमानत याचिका खारिज

रांची, 30 जुलाई (एजेंसियां)। उच्चतम न्यायालय ने रांची में सेना की जमीन की बिक्री से जुड़े एक मामले में शहर के पूर्व उपयुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह पिछले वर्ष अक्टूबर में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। रांची के बरैतू इलाके में 4.55 एकड़ सेना की जमीन को बेचने में कथित रूप से संलिप्तता के लिए चार मई को शहर में कई जगह छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रंजन को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पिछले महीने कहा था कि रांची में चेरायर होम रोड, पारु और सिरम स्थित तीन भूखंडों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है, जिनकी बाजार में कीमत 161.64 करोड़ रुपये है।

सीएम हेमंत सोरेन ने तस्वीर साझा कर दर्द किया बचां

बोले- जेल में रहने के दौरान सबसे दुःखद था बच्चों से दूर रहना



रांची, 30 जुलाई (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दायर अपील याचिका खारिज होने से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम

न्यायालय का आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो दिल को छू लेने वाली है। इन तस्वीरों में एक पिता का दर्द सामने आया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में कहा कि पांच सामने आया है। जेल में रहे तो इस दौरान अपने बच्चों को उन्होंने कितना याद किया। उन्होंने लिखा है- 'माननीय हाई कोर्ट के बाद अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। मैं हमेशा मानता हूं कि सत्य को थोड़े समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। 5 महीनों के जेल के दौरान जो सबसे ज्यादा दुःखद था वो था अपने

बच्चों से दूर रहना। सत्यमेव जयते।'।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुद्दा विधानसभा में भी गुंजा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय बता रहा है कि ईडी ने मनगढ़ूंत केस किया। इस कृत्य से झारखंड का महत्वपूर्ण समय नष्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबुलाल मरांडी और इनके सांसद निशिकांत दुवे ने पहले ही कहा था कि पूरा परिवार जेल जाएगा। साजिश के तहत इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा। अब जब सब स्पष्ट हो गया है, तो भाजपा के लोग कान पकड़कर माफ़ी मांगें। अपने-अपने मुद्दों को लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्य सदन में पहुंच गए तो स्पीकर ने पूर्वाहन 11 बजकर 27 मिनट पर पुर्वहन 12.30 तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

राज्यपाल हरिचंदन की विदाई

विश्वभूषण बोले- आप सभी पर भगवान जगन्नाथ की बनी रहे कृपा, आज रायपुर पहुंचेंगे नए गवर्नर रामेन डेका



रायपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में विदाई दी गई। वे आज भुवनेश्वर (ओड़िशा) के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थीं। राज्यपाल को गाई ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सभी

यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पंडेय और उपसचिव हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल रामेन डेका आज रायपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत कर सकते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा 31 जुलाई को नए राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ये कार्यक्रम रायपुर के राजभवन में आयोजित होगा।

किरंदुल बाढ़ पीड़ित बोले-पाई-पाई जोड़कर बनाया घर तबाह हो गया

मजदूर पिता ने कहा-पत्नी, 2 बेटियां और उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी, अब क्या खाऊं, क्या खिलाऊं

दंतेवाड़ा, 30 जुलाई (एजेंसियां)। 'मैंने दिन-रात मजदूरी की, हाथों पर छाले पड़ गए। पाई-पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब सिर ढकने के लिए न छत बची है, न खाने को दाना और न पहनने को कपड़ा है। सोना-चांदी भी पानी के साथ बह गया। अब बची है तो सिर्फ 'जिंदगी'।

'बड़ी मुश्किल से 2 बेटियों की शादी की। एक के पति की मौत हो गई, दूसरे ने उसका साथ छोड़ दिया। दोनों बेटियों समेत उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन अब बरबाद हो गया हूं। समझ नहीं आ रहा खुद क्या खाऊं, उन्हें क्या खिलाऊं, परिवार को कैसे पालूँ? ये दर्द है किरंदुल बाढ़ पीड़ित एक मजदूर पिता का। 21 जुलाई की शाम तक बंगाली कैंप में सुभाष का खुद का घर था। 3 से 4 बजे के बीच बैलाडीला



पहाड़ी पर बने एनएमडीसी 11-सी प्लांट से आई बाढ़ ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। घर ढह गया, सामान बह गया। फिलहाल प्रशासन ने इनके पूरे परिवार को मंगल भवन में रखा है। यहां अस्थायी व्यवस्था की गई है। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर और रात का खाना परिवार को दिया जा रहा है। कुछ कपड़े दिए गए हैं। ये परिवार कब तक यहां रहेगा या भरपेट भोजन कब तक मिलेगा, ये इन्हें भी नहीं पता। जब हम इसी

मंगल भवन में पहुंचे तो एक कमरे में सुभाष का पूरा परिवार था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द लिए सुभाष एक कोने में बैठे थे। टकटकी लगाकर अपने परिवार और बच्चों की तरफ देख रहे थे। चेहरे पर सिर्फ बेवसी और लाचारी थी। आपदा में

सोचने, समझने की ताकत भी जैसे खत्म हो चुकी है। सुभाष रोते हुए कहा- 'मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। बूढ़े दोस्तों पर परिवार का बोझ है। कमर झुक गई है, दर्द रहता है, बीमार हूं। दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। हालांकि, पत्नी लाइस बंधा रही है। बच्चों के चेहरे देख जी रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? उम्मीद है सब कुछ पहले की ही तरह हो जाएगा।'

डिप्टी रजिस्ट्रार ने माना-वर्कर्स कॉलेज के भवनों की स्थिति बेहद खराब

जमशेदपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। आजसू छात्र संघ और अभाविप द्वारा सोमवार को जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में जोरदार हंगामा किया गया। दोनों छात्र संगठन कॉलेज की आधारभूत संरचना की जर्जर स्थिति से नाराज हैं। यह हंगामा जिस समय हुआ, उस समय कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार एमके मिश्रा भी मौजूद थे। वे विभागीय काम से यहां आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही छात्र संगठनों के नेताओं को इसकी सूचना मिली, वे प्रिंसिपल कक्ष तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उसके बाद छात्र संघ के प्रतिनिधि प्राचार्य कक्ष में घुस गए। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से कॉलेज परिसर व क्लास रूम का अवलोकन करने को कहा। करीब आधा घंटा हंगामे के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार माने और पूरे कॉलेज का अवलोकन किया। उन्होंने कहा-वास्तव में कॉलेज के सभी भवन की स्थिति बेहद खराब है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से इसमें

सुधार के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा, करेगा। इस हंगामे में हेमंत पाठक, साहेब गवाती, राहुल पाठक, सतीश, शुभम राज, सौरव ठाकुर, विशाल सिंह आदि शामिल थे। सोमवार को कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक बैठक की। इसमें तय हुआ- जल्द ही वे उपयुक्त से मिलकर कॉलेज के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। विद्यार्थियों की मानें तो अभी कॉलेज के पास सिर्फ एक एकड़ जमीन है, जो कॉलेज संचालन के लिए बहुत कम है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि फौरन कॉलेज के अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराए। छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा-अभी तक विश्वविद्यालय का रवेया सकारात्मक नहीं रहा है। बार-बार शिकायत के बाद भी कॉलेज की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इस वजह से स्टूडेंट्स खोफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आए दिन कॉलेज के किसी न किसी भवन का छज्जा टूटकर गिर रहा है।

बस्तर की महिला भाजपा नेता बोली-मैं पार्टी में रहकर असुरक्षित

वीडियो में रोते हुए कहा- मीरा तिवारी बदनाम कर रही, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं



सेकेंड का यह वीडियो बनाया है। वीडियो में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की बात कह रही हैं। बर्बात कह रही हैं कि दंतेवाड़ा के एमएलए चैतराम अय्यामी को भी पता है, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे

बस्तर की महिला भाजपा नेता

वीडियो में रोते हुए कहा- मीरा तिवारी बदनाम कर रही, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं

प्रताड़ित किया गया है। बर्बात ने कहा कि भाजपा मेरी रक्षा नहीं कर पा रही है, वह किसी और की रक्षा क्या ही करेगी। भाजपा पार्टी में रहकर भी मैं सुरक्षित नहीं हूं। उनका कहना है कि मुझसे कोई बात नहीं करता। कोई अपने पास बैठाता नहीं है। उन्हें लगता है कि वे बदनाम जो जाएंगे। मेरी बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं मर गई तो जिम्मेदार मीरा तिवारी होगी। बर्बती गिरी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीरा तिवारी से भी हमने बातचीत की। मीरा का कहना है कि पिछले 35 साल से भाजपा संगठन में हूं, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझ पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया है।

कल्पना सोरेन ने मेडन स्पीच में एनडीए को करा दिया चुप

बोलीं- आई .एन .डी .आई .ए. अपने काम और बीजेपी झूठ के नाम पर मांगेंगी वोट

रांची, 30 जुलाई (एजेंसियां)। झारखंड विधानसभा में मौनसून सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने-अपने मुद्दों को लेकर आमने-सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ, सहायक पुलिसकर्मियों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज और सरकारी पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के निर्मित के उल्लंघन जैसे मुद्दों को लेकर वेल में जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और शामुमो के विधायकों ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उन्हें पांच महीनों तक जेल में रखे जाने का

आरोप लगाते हुए भाजपा से माफी की मांग की। वहीं गांडेय विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने अपने मेडन स्पीच में बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा।

झारखंड विधानसभा मौनसून सत्र के तीसरे दिन गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने अपने मेडन स्पीच में पहला मेडन स्पीच दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले अनुपूरक बजट पर अपने भाषण में उपचुनाव में समर्थन ईंडिया अलायंस के नेताओं-कार्यकर्ताओं का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी-एनडीए नेताओं को जनता सबक सिखाने का काम करेगी।



उपचुनाव से पूर्व राजस्थान सरकार ने खोला पिटारा

दौसा, 30 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान विधानसभा में परिवर्तित बजट में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं कर दौसा जिले को सौगातें दी। इससे अलग क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम घोषणाएं होने से लोगों में नाराजगी थी, जो अब दूर की गई है।

मुख्यमंत्री ने दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे आगामी वर्षों में दौसा में सीवर लाइन डलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गौरतलब है कि दौसा में सीवरेज के लिए कई सालों से मांग उठ रही थी, लेकिन पानी और जनसंख्या के आंकड़ों के चक्कर में मामला अटका हुआ था। अब भजनलाल सरकार ने सीवरेज मास्टर प्लान के लिए

दौसा को ये मिली सौगातें



राशि जारी कर शहरवासियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। इसी तरह शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर पर रोप-वे की घोषणा की गई है। सावन माह में महादेव के भक्तों को सरकार ने यह भी प्रमुख सौगात दी है। इससे देवगिरी तक पहुंचने में भक्तों को सहूलियत होगी।

बजट रिप्लाइं भाषण में जिले के दौसा व महुवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर ही अधिकतर घोषणाएं हुई हैं। इसके उपचुनाव को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं लालसोत और बांदीकुई क्षेत्र खाली रहा। सिकराय को कुछ

सौगातें मिली हैं।

दौसा शहर में सीवरेज, नीलकंठ रोप वे सहित अन्य विकास कार्यों के लिए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना व पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री से मांग की थी। डॉ. किरोड़ी ने गत 18 जुलाई को पत्र में जो 8 मांग की थी, उनमें से 6 सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने पूरी की हैं। इधर शंकर शर्मा ने दौसा को दी गई सौगातों को लेकर मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का आभार जताया है। विधायक राजेंद्र मीणा ने बताया कि महुवा क्षेत्र को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए तथा खोहरा मुल्ला एवं मातासुला के मध्य 400 केवी जीएसएस की घोषणा की गई है। बालाहेड़ा में कृषि महाविद्यालय व गोहंड़ी मीना में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत, खोहरा मुल्ला को उप तहसील बनाया गया है। इन घोषणाओं से क्षेत्र में खुशी की लहर है। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में 400 केवी जीएसएस बनने के बाद विद्युत संकट का समाधान हो जाएगा। खोहरा मुल्ला उप तहसील से एक दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

विधानसभा में गाली देने पर धारीवाल को मिली सजा

माफी मांगी, दो दिन कार्यवाही में हिस्सा लेने पर रोक; स्पीकर बोले- चार साल सदस्य रहने का हक नहीं

जयपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान गाली देने के मामले में मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांग ली है। माफी के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को दो दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है।

स्पीकर ने धारीवाल से कहा- आज और कल आप विधानसभा तो आएंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं तो चाहता था जिस तरह का आचरण था,चार साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने फैसला किया।

स्पीकर ने कहा- जिस तरह का आचरण किया गया, इससे सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंची, आपको अंदाजा नहीं है, जब मीडिया में यह बात गई तो इस सदन की क्या गरिमा रह गई? इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे से चेतावनी है कि आप आचरण ठीक रखें। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के किसी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इससे पहले धारीवाल के गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने सदन में माफी मांगी।

सदन में धारीवाल के गाली के मामले में स्पीकर की व्यवस्था से पहले चर्चा हुई। डोटोसरा और जुली ने स्पीकर से धारीवाल को माफ करने का आग्रह किया। जुली और धारीवाल खुद खेद प्रकट कर देंगे, उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए।

डोटोसरा बोले- धारीवाल के शब्दों को उचित नहीं ठहरा सकते

डोटोसरा ने कहा- इनके (धारीवाल) मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकले, उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते। अवस्था की वजह से निकले या कैसे निकले। हजारों बार असंसदीय शब्दों का प्रयोग होता है तो सभापति या अध्यक्ष कार्यवाही से निकाल देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। संदीप शर्मा सभापति थे, उनके बारे में बात थी, वो कार्यवाही से निकाल देते तो मामला खत्म हो जाता।

राजेंद्र पारीक जब सभापति की कुर्सी पर थे, तो उन्होंने वे शब्द कार्यवाही से हटा दिए थे। स्पीकर ने व्यवस्था देने की बात कही, हम तो निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने हा- 29 जुलाई को मुख्यमंत्री जी रोहित बोहरा को



ने धारीवाल जी की उम्र 19 साल बता दी, उसका भी असर हुआ। मेरी धारीवाल साहब से बात हुई, इनके संदीप शर्मा से अच्छे रिश्ते हैं, जब सभापति की कुर्सी पर बैठे दिखें तो कुछ कुछ शब्द निकल गए, वो शब्द गलत थे। हम सब लोग यह मानते हैं कि सदन चले, हम लोग माफी चाहते हैं, जानबूझकर नहीं किया। धारीवाल पांच बार चुनकर आए, संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो आदमी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। इन्होंने कोटा को चमकाने का काम किया। इस बात को यहीं समाप्त किया जाए।

मुख्य सचेतक बोले- सजा भी 19 साल के युवक जैसी दें क्या, यह कुतर्क है

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जब 19 साल के हैं तो सजा भी वैसी ही दी जाए। फिर तो इन्हें हाथ ऊपर करवाकर

संबोधित कर रहे थे, उनके मुंह से विवेक निकल गया, लेकिन उनकी मंशा खराब नहीं थी।

स्पीकर ने धारीवाल को 19 साल का बता दिया, उसका भी असर हुआ

डोटोसरा ने कहा- स्पीकर साहब

धारीवाल ने कहा- मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं, मैंने हमेशा इस आसन को सर्वोच्च मानकर ही चला हूं। मेरा आसन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। संदीप शर्मा जब पहली बार सभापति की कुर्सी पर बैठे तो इस पूरे सदन में अकेला आदमी था, जिसने कहा था आज सबसे ज्यादा खुश हूं

कि ये विराजमान है। जहां तक संदीप शर्मा की बात है तो वो मेरे बेटे के दोस्त हैं। हमेशा हंसी मजाक चलती रहती है। जब भी मिलते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं।

विधानसभा कार्यवाही के दौरान नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए ऐसे ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी है। स्पीकर ने विधायकों के सवाल वापस लेने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब सवाल वापस लेना होता है तो लगाते ही क्यों हो। इस बार पक्ष-विपक्ष के 7-8 विधायकों के सवाल लेने के प्रस्ताव आए हैं। आगे से सवाल वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जोधपुर शहर को मिलीं सौगातें, बदलेगी सूरत

जोधपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान जोधपुर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। सांघिया में नया सेटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा। इससे सांघिया और आसपास के ग्रामीणों को घर के पास चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार ने संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में सरम्मत कार्य कराने के लिए फण्ड दिया है। इससे एमडीएम अस्पताल में

सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मेलबा (धवा) और मणाई (केरू) को उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

इसके अलावा चर्चा के दौरान झंवर में नया राजकीय कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई।

प्रदूषण नियंत्रण का नया कार्यालय खुलेगा

जयपुर और जोधपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे।

जोधपुर में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए लंबे समय से प्रदूषण

नियंत्रण की और आवश्यकता महसूस हो रही थी।

इसके अलावा इन दोनों कार्यालयों में एडर्जिक्टिंग ऑफिसर का नया पद सृजित किया जाएगा।

पैनोरामा भी

राज्य सरकार ने बजट पर चर्चा के दौरान कई पैनोराम की भी घोषणा की।

इसमें जोधपुर में राव चंद्रसेन का पैनोरमा भी चिकसित किया जाएगा। ग्राम चौखा (लूणी) में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय खोलने की घोषणा की गई।

नाथद्वारा में 37 दिन में बनी बिल्डिंग गिरी, 4 की मौत तहसीलदार बोले-अवैध निर्माण था, ईंटों के पिलर पर बनाया था स्ट्रक्चर

नाथद्वारा, 30 जुलाई (एजेंसियां)। राजसमंद जिले में नाथद्वारा के चिकलवास गांव में सोमवार रात 11 बजे सामुदायिक भवन की छत गिरने से चार ग्रामीणों की दबने से मौत हो गई। यहां 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर गांव के 13 लोग साफ-सफाई करने आए थे। शाम 37 दिन में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। बिल्डिंग के सभी लैटर सोमवार शाम को ही हटाए गए थे।

हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर 9 लोगों को मलबे से निकाला। सभी की हालत गंभीर है। इन्हें नाथद्वारा के लालबाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।

नाथद्वारा के तहसीलदार भानु प्रताप सिंह का कहना है कि चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण कर सामुदायिक भवन बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य 22 जून से शुरू हुआ था। स्ट्रक्चर लगभग 300 वर्ग गज में बनाया गया था। पिलर्स पर आरसीसी की छत डाली

हुंथे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर 9 लोगों को मलबे से निकाला। सभी की हालत गंभीर है। इन्हें नाथद्वारा के लालबाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।

नाथद्वारा के तहसीलदार भानु प्रताप सिंह का कहना है कि चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण कर सामुदायिक भवन बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य 22 जून से शुरू हुआ था। स्ट्रक्चर लगभग 300 वर्ग गज में बनाया गया था। पिलर्स पर आरसीसी की छत डाली

डोडा पोस्ट तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुआ था बदमाश



सिरोही, 30 जुलाई (एजेंसियां)। बीती 12 जुलाई को पिंडवाड़ा पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान जयपुर पांसिंग की एक कार से पुलिस ने 268 किलो डोडा पोस्ट मिलने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था लेकिन वाहन चालक मुख्य आरोपी पुलिस पर फायरिंग करके मौके से फरार हो गया था। रोहिड़ा थाना पुलिस ने आज कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कॉन्स्टेबल ब्रवण कुमार, शंकरलाल, रामलाल एवं बजरंगलाल द्वारा की गई। मामले में बाइमेर निवासी लक्ष्मणराम पुत्र मंगनाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को खिलाफ रोहिड़ा थाने में एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है।

दो साल से फरार दस हजार का इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हनुमानगढ़, 30 जुलाई (एजेंसियां)। महिला थाना पुलिस ने दो साल से फरार चल रहे दस हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। महिला से छेड़छाड़ व जातिसूचक गालियां निकालने के आरोप की पुलिस निरंतर तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी में हैड कॉन्स्टेबल सुखविन्द सिंह की विशेष भूमिका रही। जांच अधिकारी एससीएसटी सेल सीओ रणवीर साई ने बताया कि वर्ष 2022 को महिला ने मामला दर्ज कराया था कि महेन्द्र कुमार गोदारा (35) पुत्र रामचंद्र गोदारा निवासी 22 एनडीआर पीएस टाउन ने उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाणी की तथा जातिसूचक गालियां निकालीं। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। वह टाउन थाना का भी स्थाई वार्डरी है। महिला थाने में दर्ज मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी महेन्द्र कुमार जिले के टॉप-10 वॉलंटों में शामिल थिए। उस पर तीन-चार मुकदमे दर्ज



बताए गए हैं।

हनुमानगढ़. मजदूर से ठगी के आरोपी ठेकेदार को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। गहन पूछताछ के लिए उसका तीन दिन का रिमांड मंजूर कराया गया। पुलिस के अनुसार रमेश कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा ने 16 जुलाई को मामला दर्ज कराया था कि ठेकेदार मनप्रीत पुत्र गुरतेज सिंह निवासी खरलिया के जंक्शन में सूरतगढ़ रोड स्थित गणपति कॉलोनी में चल रहे

निर्माण कार्य पर उसने मजदूरी की थी। उसने 15 मार्च से 3 जून तक मजदूरी की जो 400 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से तय की गई थी। आरोप है कि ठेकेदार ने छह हजार रुपए कम मजदूरी दी। बाद में सख्त जरूरत बताकर उसने 53 हजार रुपए उधार ले लिए। उक्त राशि भी उसने लौटाने से इनकार कर दिया। आज कल करता रहा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मनप्रीत सिंह (28) पुत्र गुरतेज सिंह निवासी खरलिया को गिरफ्तार कर लिया।

घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर दंपती पर किया जानलेवा हमला

बारां, 30 जुलाई (एजेंसियां)। कल शाम दो नकाबपोश बदमाश डॉक्टर दंपती के घर में घुसे और चाकू से हमला कर कोर्ट में पेश किए गए। बदमाश डॉक्टर दंपती के मेडिकल स्टोर के कर्मचारी के पीछे-पीछे घर में घुसे थे और नकदी, जेवर समेत कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

घटना डॉ. उषा अग्रवाल और डॉ. सत्येंद्र अग्रवाल के घर पर हुई, जहां वे मरीजों को परामर्श भी देते हैं। यहीं पर उनका एक मेडिकल स्टोर भी है। शाम को मेडिकल स्टोर का कर्मचारी

दवाइयों का हिसाब देने उनके घर गया था तभी पीछे से आए दो नकाबपोश बदमाशों ने डॉ. उषा अग्रवाल पर चाकू से हमला कर दिया, फिर डॉ. सत्येंद्र अग्रवाल को चाकू दिखाकर धमकाया। इसके बाद घर से नकदी और जेवर समेत अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात में मेडिकल स्टोर के कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध है और उससे पूछताछ की जा रही है।

जेलर को सबक सिखाने के लिए रची साजिश बोला..ऐसा काम करूंगा कि यह पेंशन नहीं ले पाएगा...

दौसा, 30 जुलाई (एजेंसियां)। दौसा की श्यालावास जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी जिस सिम से दी गई, वह चार माह पहले ही जेल में पहुंचाई गई थी। जेल में कैदियों को बिजली उपकरण सुधारने की ट्रेनिंग देने वाले ने इसके बदले बंदी रिकू की मां से पांच सौ रुपए लिए थे। दौसा पुलिस ने ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। सिम रिकू से बंदी दौलत और फिर नीमा को मिली, जिसने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। यह भी जानकारी में आया है कि नीमा बार-बार कहता था कि जेलर को सबक सिखांना है। उसने यह धमकी जेलर के सेवानिवृत्त होने के चार दिन पहले दी है, जिसके बाद सरकार ने जेलर को निलंबित कर दिया। पुलिस जेल से मिली इस सूचना की पुष्टि करने में जुटी है। जयपुर की विधायकपुत्री थाना पुलिस ने नीमा व जेल में सिम मंगाने वाले रिकू को जेल से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि पचास



वर्षीय राजेन्द्र से जेल में ट्रेनिंग के दौरान होली से पहले बंदी रिकू ने उसके घर पर जाकर मां से मिलने के लिए कहा था। राजेन्द्र रिकू की मां से मिला। रिकू की मां ने राजेंद्र को सिम दी थी। जेल में सिम पहुंचाने के लिए पांच सौ रुपए भी दिए। राजेन्द्र कपड़ों में छिपाकर सिम जेल में ले गया था। सिम रिकू की मां के नाम से ही जारी कराई गई थी।सिम दी तो बीड़ी-गुटखे का बकाया माफ्रिकू ने धुलंडी के दिन सिम उसी वार्ड में कैद दौलत को दी थी। दौलत जेल में बंदियों से मोटी रकम लेकर बीड़ी व गुटखा उपलब्ध कराता है। रिकू को उसे

रुपए चुकाने थे। बकाया चुकाने के बदले उसने सिम दे दी। दौलत ने यह सिम नीमा को दी थी, जिसने दो दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम कॉल कर धमकी दी थी। शनिवार देर रात जयपुर पुलिस के कंट्रोल रूम पर कॉल कर बंदी नीमा ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी।

नीमा इस जेल में कई वर्ष से कैद था। वह दौलत से बीड़ी और गुटखा लेता था। इसका कर्जा चढ़ गया था। वह रुपए देने की स्थिति में नहीं था। इसी दौरान उसने यह साजिश रची। उसे यह जानकारी थी कि जयपुर जेल से भी इसी

तरह की धमकी दी गई थी, जिसके बाद जेल में हलचल मच गई थी। नीमा शुक्रवार को कई बंदियों को कह चुका था, बहुत हुआ अब उसे कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। सबको देख लूंगा। शनिवार रात को उसने धमकी दे डाली। इसके बाद दौसा जेल के कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश दरोगा, कारापाल बिहारीलाल व प्रहरी अवधेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया।

दोनों आरोपी बलात्कार और पोक्सो केमामले को लेकर तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। धमकी को लेकर जयपुर के विधायकपुत्री थाने में मामला दर्ज किया है, जिसमें नीमा व रिकू को गिरफ्तार किया गया। वहीं दौसा ने पापड़दा थाने में सिम को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। जेल में मिले अन्य दस मोबाइल को लेकर पापड़दा थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। जेल में कैद सभी आरोपी बलात्कार व पोक्सो के मामलों में गिरफ्तार हुए थे।

कांवड़ियां ले जा रहे मामा-भांजे की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

धौलपुर, 30 जुलाई (एजेंसियां)। धौलपुर में सोरों उग्र घाट से गंगाजल भरकर डांक कांवड़ ला रहे युवाओं को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक उस ट्रॉली से भिड़ गया जिसमें अन्य कांवड़िए साथ चल रहे थे। इस भीषण हादसे में मामा-भानजे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि करीब दो दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। इनमें से गंभीर हालत में आधा दर्जन को ग्वालिगर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक ने अनियंत्रित होकर हाइवे स्थित देवरी घडियाल केन्द्र के पास डांक कांवड लेकर दौड़ रहे युवाओं को बचाने के चलते ट्रक ट्रॉली में भिड़ गया। ट्रॉली में सवार छोट्ट पुत्र भरतलाल शर्मा निवासी गढिया सिहोनियां एवं उसका भानजा आशु पुत्र रामनरेश शर्मा निवासी लालौर हाल यादव कॉलोनी मुरैना की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित कांवड़ियों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं चालक समययदीन खान निवासी पहाड़ी निवासी भरतपुर राजस्थान के बसबॉल व डंडों से मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसे बचाया। हादसा होने ही सिविल लाइन पुलिस की मोबाइल व स्टफ तुरंत मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक जाम लग चुका था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद सुबह पांच बजे लगा जाम साढ़े सात बजे खुलवाया जा सका।

ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा नकली तेल सीज

कोटा, 30 जुलाई (एजेंसियां)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा में बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने रानपुर में शिवम एंडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में छाप मारा और करीब साढ़े 7 हजार लीटर तेल पकड़ा है।

यहां पर तेल को प्रोसेस करके अलग-अलग ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके से निवाई, राजस्थान, पोस्टमैन समेत अन्य ब्रांड के नकली तैयार किए गए तेल के पीपे, पैकिंग, समेत अन्य सामग्री जप्त की हैं।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया- कुछ समय पहले विभाग की टीम ने यहां से सैपल लिए थे, जो जांच में सबस्टैंडर्ड के मिले। यहां ब्रांडेड के नाम से मिलावटी तेल बेचने की सूचना मिल

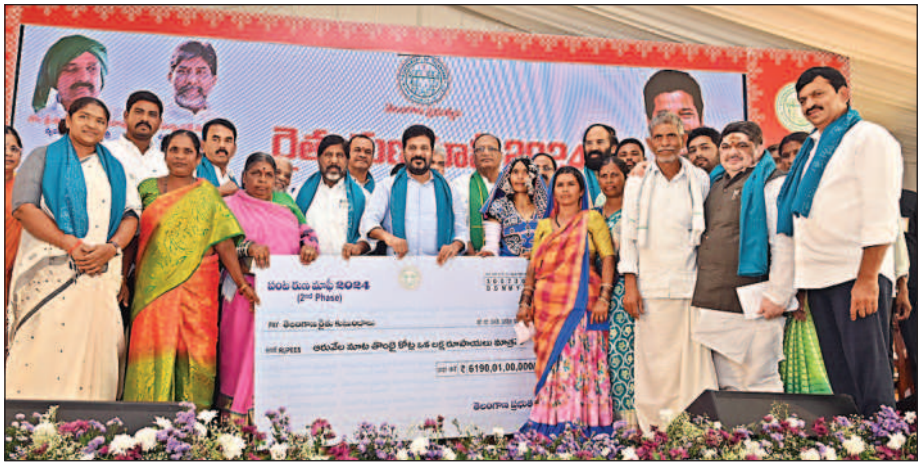
रही थी। जिस पर आज टीम के साथ मौके पर आए। देखा तो एक ही तेल को अलग-अलग ब्रांड के नाम से पैक किया हुआ था। इसमें मुख्यतः मूंगफली और तिल्ली का तेल था। संदेह के आधार पर टीम ने 450 लीटर तिल्ली के तेल सहित साढ़े 7 हजार लीटर तेल सीज किया है। टीम ने मौके से सैपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पंकज ओझा ने बताया निवाई, बीकानर, कोटा, ब्यावर सहित अन्य जगहों से कच्चा माल लाता था। उन्हें अपने यहां 5-6 ब्रांड से पैक किया जा रहा था। फिर ब्रांडेड बताकर कोटा और बाहर सप्लाय किया जा रहा था। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि ये माल कोटा, बूंदी सहित हाड़ौती सम्भाग में दुकानदारों को 100 रुपए लीटर में सप्लाय करता था।

कृषि ऋण माफ करना देश के इतिहास में नया रिकॉर्ड : रेवंत रेड्डी

> तेलंगाना सरकार ने 12 दिनों में 12,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए

> कृषि ऋण माफी के दूसरे चरण के तहत धनराशि जारी की



हैदराबाद 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आज यहां कहा कि अगस्त में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसी महीने तेलंगाना राज्य के किसानों को भी बढ़ते कर्ज के बोझ से मुक्ति मिली और 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ होने से कृषक समुदाय को राहत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई और अगस्त को देश के इतिहास में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय महीनों के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मात्र 12 दिनों में 12,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करके किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण और किसानों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं के प्रति सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत कोई भी कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार में 31,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करके कृषि ऋण माफ करना देश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। देश के इतिहास में अब तक किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी राशि के किसानों के कर्ज माफ नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल आमतौर पर चुनाव के समय किसानों को याद करते हैं और उन्हें वादों के साथ लुभाते हैं। आज, न तो चुनाव हैं और न ही संकटग्रस्त किसानों के हितों की रक्षा के अलावा कृषि ऋण माफी में कोई राजनीतिक हित है। विधानसभा सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज (मंगलवार) दोपहर विधानसभा परिसर में 1.50 लाख रुपये तक के दूसरे चरण की कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, विधानसभा अध्यक्ष गड्डाम प्रसाद, परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी,

कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव, राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने किसानों को चेक वितरित करने में भाग लिया और पूरे परिसर में उत्सव का माहौल रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 6.40 लाख किसानों के खातों में सीधे 6198 करोड़ रुपये जमा करके सभी किसानों का 1.50 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों के जीवन में खुशी देखकर मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। किसान ऋण माफी योजना के तहत, सरकार ने 18 जुलाई को पहली किस्त में 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि माफ कर दी। कुल 11 लाख किसानों को 6098 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफी लाभ मिला। 12 दिनों के भीतर दूसरी किस्त के रूप में 6198 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं। कार्यक्रम में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ-साथ भाकपा और भाजपा विधायकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पार्टी से जुड़े सभी नेताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 6 मई, 2022 को वाराणस में किसान घोषणापत्र की घोषणा की और कृषि को एक लाभदायक पेशे के रूप में बढ़ावा देने का वादा किया। कांग्रेस के वादे के अनुसार, सरकार ने सत्ता में आने के बाद मात्र आठ महीने में ही किसानों का कर्ज माफ कर उनके जीवन में खुशियां भर दी हैं। सीएम ने कहा कि देश में कुछ कॉर्पोरेट संगठनों ने बैंकों से कर्ज लिया और खुद को दिवालिया घोषित कर धोखाधड़ी की। पिछले दस सालों में कंपनियों ने बैंकों का 14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया। जबकि पूरे देश का पेट भरने वाले किसान अच्छी उपज, लाभकारी मूल्य न मिलने और बढ़ते कर्ज को चुकाने

में असमर्थ होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दुख जताया कि आत्मसम्मान खोने के कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। यही कारण है कि कांग्रेस ने दो लाख रुपये तक के कृषि कर्ज को माफ करने का वादा किया और परेशान किसान परिवारों में खुशियां भर दीं। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछली सरकार एक लाख रुपये तक के कृषि कर्ज को लागू करने में विफल रही। पिछली सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में चार किस्तों में कृषि कर्ज माफ किया और किसानों को अपने कर्ज पर अधिक ब्याज देकर परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरे कार्यकाल में बीआरएस सरकार ने एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का यही वादा किया, लेकिन 19,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले केवल 12,000 करोड़ रुपये जारी किए। पिछली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संकट के बीच कृषि ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन पर कुछ लोगों ने सरकार का मजाक उड़ाया और कुछ ताकतों ने सरकार को कोसा। मेरी सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई और अगस्त तक कृषि ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की योजना के अनुसार वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान के नारे के साथ देश में हरित क्रांति लाई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि भाकनंगल से

नागार्जुनसागर तक की परियोजनाएं किसानों के लाभ के लिए बनाई गई थीं, इंदिरा गांधी ने गरीब किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, 72,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए और किसानों का समर्थन किया। यह एकमात्र कांग्रेस सरकार थी जिसने सब्सिडी पर बीज, उर्वरक, मुक्त बिजली, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया। कांग्रेस देश में किसानों की हितैषी पार्टी साबित हुई। वादे के मुताबिक, सीएम रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया कि इस साल अगस्त तक एक महीने के भीतर 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने भारी कर्ज लेकर राज्य को गिरवी रख दिया। कांग्रेस सरकार राज्य को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए प्रयास कर रही है। उनकी सरकार ने महज आठ महीने में 7 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए 42,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और उनकी टीम की प्रशंसा की, जिन्होंने 12 दिनों में 12,000 करोड़ रुपये जुटाए और किसानों के खातों में जमा करवाए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आरोग्यश्री, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली आपूर्ति, 500 रुपये में गैस सिलेंडर शामिल हैं और चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा घोषित छह गारंटियों को पूरा करने में सरकार की ईमानदारी दिखाई।



जीआईएस मैपिंग के हिस्से के रूप में फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण शुरू

जीएचएमसी ने लोगों को सहयोग करने की अपील की

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। जीएचएमसी के तहत संपत्तियों और उपयोगिताओं के जीआईएस मैपिंग सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में क्षेत्र स्तरीय सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है। शहरी नियोजन के तहत एकीकृत जीआईएस सर्वेक्षण मंगलवार से शुरू हो गया है। इस पृष्ठभूमि में, सटीक मानचित्रण के कारण हैदराबाद में सभी संपत्तियों और उपयोगिताओं का विवरण भौगोलिक रूप से पहचाना जाता है। टेक्स वसुली भी आसान होगी। कहा जा सकता है कि इससे प्रॉपर्टी टेक्स से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी और ऑनलाइन भुगतान आसान हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग से सड़कों, पार्कों और अन्य सुविधाओं का विवरण स्पष्ट हो जाता है। कई सर्किलों में फील्ड लेवल सर्वे आज (मंगलवार) से शुरू हो गया है और यह फील्ड सर्वे उपपल, हयात नगर, हैदर नगर, कृष्णकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, मियापुर और चंदनगर इलाकों में किया जा रहा है। शहर के अन्य सभी हिस्सों में सर्वेक्षण जारी रहेगा। संसाधन प्रबंधन के लिए जीएचएमसी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में मकान मालिकों को सहयोग करने के लिए कहा गया है। जीएचएमसी ने सर्वेक्षण कर्मचारियों से मांगी गई जानकारी प्रदान करने को कहा। सर्वेक्षण का विवरण पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। जीएचएमसी ने क्षेत्र स्तरीय सर्वेक्षण के लिए अपने वाले कर्मियों से बिल्डिंग परमिट, अधिभोग प्रमाण पत्र, नवीनतम भुगतान संपत्ति कर रसीद, नाला बिल, बिजली बिल, मालिक आईडी विवरण, व्यापार लाइसेंस संख्या (वाणिज्यिक भवन) विवरण प्रदान करके सहयोग करने के लिए कहा है। ड्रोन सर्वे के तहत दोबारा घर-घर जाकर भवन संरचनाओं की जांच की जाएगी।

साइबराबाद आयुक्त कार्यालय में घरेलू हिंसा समन्वय बैठक आयोजित

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। साइबराबाद आयुक्त कार्यालय के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला एवं बाल सुरक्षा विंग (डब्ल्यूएंडसीएसडब्ल्यू) डीसीपी सृजना कर्णम द्वारा घरेलू हिंसा पर समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शी टीएम, मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू), सखी केंद्र और भरोसा केंद्र के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रयासों का समन्वय करना और सहायता प्रणालियों को बढ़ाना है, ताकि व्यापक और समय पर सहायता सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान, डीसीपी सृजना कर्णम ने घरेलू हिंसा पर सहयोगात्मक चर्चा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी और संगारेड्डी जिलों के जिला कल्याण अधिकारियों के साथ-साथ सखी केंद्रों और महिला विकास और सशक्तिकरण केंद्र (सीडीडबल्यू) केंद्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। चर्चा का मुख्य



उद्देश्य समन्वय को बढ़ाना और घरेलू हिंसा को संबोधित करने और रोकने के लिए प्रभावी उपाय विकसित करना था। डीसीपी ने पीड़ितों का समर्थन करने और मजबूत तंत्र तथा त्वरित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बैठक में साइबराबाद पुलिस और संबंधित कल्याण संगठनों की घरेलू हिंसा से व्यापक रूप से निपटने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया

गया। सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को आवश्यक सहायता और न्याय मिले। भरोसा केंद्रों के प्रतिनिधियों ने कहा कि घरेलू हिंसा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों से झेली गई किसी भी तरह की हिंसा शामिल है, लेकिन आम तौर पर यह किसी महिला द्वारा अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य या रिश्तेदारों के कारण झेली गई हिंसा होती है। यह दुर्यवहार जरूरी नहीं कि शारीरिक

हो। यह मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक क्षेत्रों तक भी फैल जाता है, जिससे वह टूट जाती है और अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं हो पाती। दहेज निषेध अधिनियम, 1861 से शुरू होकर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए, जिसने दहेज देने और लेने के कृत्य को अपराध बना दिया। सबसे हालिया कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) 2005 है, जो एक नागरिक कानून है जिसने घरेलू हिंसा की परिभाषा को व्यापक बनाया है। बैठक में डब्ल्यू एंडसीएसडब्ल्यू डीसीपी सृजना कर्णम, डब्ल्यू एंड सीएसडब्ल्यू इंस्पेक्टर सुनीता, एएचटीयू इंस्पेक्टर जेम्स बाबी, डब्ल्यूपीएस इंस्पेक्टर लक्ष्मरेड्डी, डीडब्ल्यूओ रंगारेड्डी पञ्चा, डीडब्ल्यूओ मेडचल-मलकजगिरी कृष्णारंजी, डीडब्ल्यूओ संगारेड्डी ललित, अन्य अधिकारी, एसआई अधिकारी, भरोसा केंद्र के प्रतिनिधि और शक्ति केंद्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चारमीनार पर लगी 130 साल पुरानी घड़ी क्षतिग्रस्त



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। ऐतिहासिक चारमीनार की पूर्वी ओर की घड़ी का सफेद डायल सोमवार को क्षतिग्रस्त हो गया। 433 साल पुराने स्मारक पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने घड़ी को हट्ट नुकसान को देखा, जिसके बारे में संदेह है कि यह नुकसान घड़ी के इर्द-गिर्द झुंड बनाकर रहने वाले कबूतरों की वजह से हुआ है। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने इसकी मरम्मत का काम शुरू किया, जो मंगलवार दोपहर तक पूरा हो गया। महबूब चौक स्थित वाहिद वॉच के गुलाम मोहम्मद रब्बानी ने अपने सहयोगी मधुसूदन चारी के साथ मिलकर 130 साल से अधिक पुरानी घड़ी की अस्थायी मरम्मत की थी। रब्बानी ने बताया कि घड़ी के डायल को हट्ट नुकसान के बारे में सूचना मिलने पर हमने आज इसकी मरम्मत

करवाई। टूटे हुए डायल को जोड़ने और इसे लगभग मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए एक विशेष गॉड पेस्ट का इस्तेमाल किया गया। चारमीनार पर चार घड़ियां 1889 में छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान के शासनकाल में लगाई गई थीं और 2 अगस्त तक हल्की बारिश का अनुमान है। हैदराबाद ने शहर में अगले 4 दिनों, यानी 2 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि दोपहर से रात तक तेज बारिश होगी। पूर्वी और मध्य तेलंगाना में रात या सुबह मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, महबूबाबाद और वारांगल में क्रमशः 99.8 मिमी और 94.5 मिमी बारिश हुई। हैदराबाद में भी आधी रात को हल्की से मध्यम बारिश हुई।

गडवाल विधायक रेड्डी मानसून के दौरान आर्द्रता 8 प्रतिशत बढ़ी

ने कांग्रेस छोड़ी बीआरएस में हुए शामिल



हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस विधायकों को अपने पाले में करने की कांग्रेस की कोशिशों में एक नया मोड़ तब आया जब हाल ही में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए गडवाल विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी ने फिर से विपक्ष में लौटने का फैसला किया। संयोग से, उन्होंने अपने फैसले की घोषणा तब की जब कांग्रेस विधानसभा परिसर में कृषि ऋण माफी की दूसरी किस्त जारी होने का जश्न मनाते में व्यस्त थी। गडवाल विधायक ने विधानसभा परिसर में पार्टी विधायी कार्यालय में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव से मुलाकात की और पार्टी में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई। मुलाकात के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। रामा राव से मुलाकात के दौरान कृष्ण मोहन रेड्डी ने घर वापसी की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीआरएस नेताओं ने उम्मीद जताई कि सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए नौ अन्य विधायकों में से अधिकांश भी बीआरएस के पाले में लौट आएंगे। वह 6 जुलाई को मुख्यमंत्री और टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि, वह कथित तौर पर पार्टी से नाखुश थे और अपने फैसले पर खेद जता रहे थे।

हालिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा

हैदराबाद, 30 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद का मानसून सीजन तेजी से आर्द्र होता जा रहा है। अध्ययन ने 2001 से 2023 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि मानसून के महीनों (जून से अगस्त) के दौरान आर्द्रता का स्तर 2001-2010 की अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत बढ़ गया है। नमी में इस वृद्धि के कारण ताप सूचकांक में मामूली वृद्धि हुई है, जो तापमान और आर्द्रता को मिलाकर यह बताता है कि गर्मी कितनी महसूस होती है। मानसून के दौरान गर्मी सूचकांक अब 2001-2010 में 1.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2014-2023 में 1.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि न होने के बावजूद, बढ़ी हुई आर्द्रता हवा को गर्म और अधिक दमनकारी महसूस कराती है। रिपोर्ट में ग्री-मानसून अवधि (मार्च से मई) के दौरान हुए बदलावों की भी जांच की गई है। इसमें पाया गया कि आमतौर पर शुष्क रहने वाला यह मौसम और भी उमस भरा हो गया है, पिछले एक दशक में आर्द्रता का स्तर 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है। हालांकि, इस अतिरिक्त नमी का ताप सूचकांक पर प्रभाव मानसून के दौरान की तुलना में कम गंभीर है। ग्री-मानसून के दौरान ताप सूचकांक में औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो पिछले दशक के 0.6

डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जो तापमान में मामूली वृद्धि दर्शाता है। आर्द्रता में इस वृद्धि के बावजूद, मानसून-पूर्व और मानसून-पूर्व दोनों अवधियों में वास्तविक तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। अध्ययन में कहा गया है कि 2001-2010 के औसत की तुलना में ग्री-मानसून और मानसून मौसम के दौरान औसत तापमान में क्रमशः 0.7 डिग्री सेल्सियस और 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। हालांकि, इन दोनों मौसमों के बीच तापीय अंतर कम होता जा रहा है, तथा समान अवधि में ताप सूचकांक में अंतर 3.1 डिग्री सेल्सियस से घटकर 2.9 डिग्री सेल्सियस रह गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैदराबाद में शहरी ताप द्वीप प्रभाव है, जहां शहर का आंतरिक भाग, बाहरी क्षेत्र की तुलना में रात में अधिक गर्म रहता है। दिन के समय, शहर का केंद्र वास्तव में अपने उपनगरीय क्षेत्रों की तुलना में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। हालांकि, रात में, स्थिति उलट जाती है, शहरी केंद्र अधिक गर्मी बरकरार रखता है और आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है। इस घटना का अर्थ यह है कि जहां शहरी क्षेत्रों में रात के समय तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, वहीं शहर का केंद्र केवल 9.7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, तथा 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्मी बरकरार रखता है।